एस०टी०सी०, एम०एम०टी०सी० और पी० ई० सी० का पुनर्गठन

1149. **श्री विनोद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मई, 1992 के "फाइनेनशियल एक्सप्रेस" में "गवर्नमेंट टू रीओरगेनाइज एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी., पी.ई.सी." शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उपक्रमों को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन उपक्रमों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इनकी भावी रूप रेखा किस तरह की होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप (मंत्री श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी. और पी.ई.एल. को मिलाकर या अन्य प्रकार से पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि अधिसंख्य निर्यात और आयात मदों के असरणीयन के परिणाम-स्वरूप इन निगमों ने अपने सामूहिक उद्देश्यों को पुनः सूत्रबद्ध किया है । जिससे कि वे मुख्यतः असरणीयकृत व्यापार पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक घराने बन सकें ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चाय का उत्पादन

1150. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चाय के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाएगा और इससे सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की तुलना में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : चाय बोर्ड ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य तथा निर्यात की प्रतिशतता निर्धारित की है जो निम्नानुसार हैं :—

(आंकड़े मि० कि०ग्रा०)

वर्ष	लक्ष्य		निर्यात की प्रतिशतता
	उत्पादन	निर्यात	
1992–93	765	221	28.89
1993–94	791	226	28.57
1994–95	818	232	28.36
1995–96	846	237	28.01
1996–97	874	243	27.80

निर्यात आयों के संबंध में लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित नहीं किए गए है क्योंकि ये आय किसी विशेष वर्ष के दौरान मूल्य प्राप्ति की अधीन होगी । प्रति इंकाई प्राप्ति मूल्य समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है जो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है । अतः सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान विश्वसनीयता से नहीं लगाया जा सकता है ।

कृषि पदार्थों का निर्यात

1151. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पदार्थों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन देने अथवा इसके विकल्प में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने का विचार रखती है ?

वाणिज्य संराज्य में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए कृषि वस्तुओं के लिए 5747 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसमें प्रसंस्कृत फलों एवं रसों और अन्य प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए 426 करोड रु० मूल्य का लक्ष्य शामिल है ।

(ख) और (ग) सरकार ने निर्यात नीति के वातावरण में सुधार लाने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए है । इन उपायों को नई आयात-निर्यात नीति द्वारा द्वारा और आगे सुदृढ़ किया गया है । यह नीति पांच वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से लागू हो गई है ।

निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु किए गए किए जाने वाले प्रस्तावित खासघ्खास उपाय इस प्रकार है :-

(क) **अल्पावधि उपाय** : बाजार-विकास, उत्पाद संवधन, क्वालिटी उन्नयन, पैकेजिंग सुधार, प्रतियोगी कीमतें निधारित करना, बाजार आसूचना बुनियादी सुविधाओं के विकास, बाधाए दूर करने और क्रियाविधि के सरलीकरण की योजनाएं ।

(ख) दीर्घावधि उपाय : उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, नए-नए बाजारों में प्रवेश करना, उत्पाद विकास, निर्यात अभिमुख प्रसंस्करण उद्योगो का संवधन, भारतीय खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता और छवि में सुधार हालांकि सरकार कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन करना चाहती है लेकिन हमारी नीति यह है कि इस कार्य को इस ढंग से किया जाए कि जनता के उपयोग की मदों की घरेलू उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े । जहां तक निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों की बात है, यह सभी निर्यातकों को उपलब्ध कराए जाते हैं, इनमें गैर-सरकारी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं ।

Import of Bulk Drugs

1152. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the details of bulk drugs imported by various firms having loan licence under actual user condition during each of the last three years;

(b) whether Government have taken steps for post import checks of such imports;

(c) if so, what are the details thereof; and